

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1720] No. 1720]

नई दिल्ली, सुक्रवार, सितम्बर १, २०११/माद्र १८, १९३३

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2011/BHADRA 18, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2011

का.आ. 2059(अ).—यतः, मै. नताशा हाउसिंग एण्ड अर्बन डेवेलपमेंट लिमिटेड, जो एक निजी संगठन है, ने हरियाणा राज्य में ग्राम कोहण्ड, तहसील घरोंडा, जिला करनाल एवं ग्राम सराय कोहण्ड, तहसील पानीपत, जिला पानीपत में हस्तशिल्प क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अन्तर्गत दिनांक 29 नवम्बर, 2010 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:---

	त		
क्र. सं.	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कोहण्ड(करनाल)	2	0.1125
2.	-	6	0.4000
. 3.		9 •	0.4000
4.		10/1	0.3850
5.		10/2	0.0400
6.		12/21	0.0700
7.		12/23	0.2500
8.		13/13	0.1275
9.		13/17/1	0.0925
10.		18/1	0.2300
11.		23/5/2	0.3150
12.		24/1	0.3900
13.		24/1/1	0.1500 4
14.		24/3	0.2225
15.		24/8/1	0.3500
16.	सराय कोहण्ड (पानीपत) 300	0.3140
17.		307	0.3333
18.		308	0.3333
19.	*	309	0.2499
20. 21		312	0.3333
21.		313	0.3333

(1)	(2)	(3)	(4)
22.		314	0.3333
23.		316	0.4173
24.		317	0.2625
25.		318/1	0.0166
26.		318/2	0.3140
27.		319	0.1528
28.		320	0.3801
29.		321	0.3333
30.	,	322	0.3333
31.		323 •	0.3333
32.		324	0.1280
33.		325	0.1652
34.		326	0.2685
35.		327	. 0.3016
36.	8.1	328	0.3333
37.	1	329	0.3140
38.	*	330	0.3333
39.		332	0.3347
		कुल	10.4872 हेक्टेयर

और यत:, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक सिमिति जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त —अध्यक्ष, पदेन

—सदस्य, पदेन

-सदस्य, पदेन

सदस्य, पर्दन

- निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा
- विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक
- 4. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा-शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- 5. विशेष आर्थिक जोन पर भू-भागीय सदस्य, पदेन क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा
- 6. निदेशक (बैंकिंग), वित्तं मंत्रालय, —सदस्य, पदेन बैंकिंग प्रमाग, भारत सरकार

- 7. राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने —सदस्य, पदेन वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
- 8. जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि —विशेष आमंत्रिती

ति विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (206: 28) जी धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा दिनांक 9 सितम्बर, 2011 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कंटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 2/143/2006-एसईजेड] अनुप वधावन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (Department of Commerce) NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2011

S.O. 2059(E).—Whereas, M/s. Natasha Housing and Urban Development Limited, a private organisation, has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for handicrafts sector at Village Sarai Kohand, Tehsil Panipat, District Panipat and Village Kohand, Tehsil Gharonda, District Karnal in the State of Haryana;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 29th November, 2010;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely:—

TABLE

SL No.	Name of the Village	Khasra No.	Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kohand (Karnal)	2	0.1125
2.		6	0.4000
3.		9	0.4000
4.		10/1	0.3850
5.		10/2	0.0400
6.	*	12/21	0.0700

(1)	(2)	(3)	(4)
7.		12/23	0.2500
8.		13/13	0.1275
9.	•	13/17/1	0.0925
10.		18/1	0.2300
11.		23/5/2	0.3150
12.		24/1	0.3900
13.		24/1/1	0.1500
14.	•	24/3	0.2225
15.		. 24/8/1	0.3500
16. Sarai	Kohand (Pani	pat) 300	0.3140
17.		307	0.3333
18.		308	0.3333
19.		309	0.2499.
20.		312	0.3333
21.		313	0.3333
22.		314	0.3333
23.		316	0.4173
24.		317	0.2625
25.		318/1	0.0166
26.		318/2	0.3140
27.	·	319	0.1528
28.	•	320	0.3801
29.		321	0.3333
30.		322	0.3333
31.		323	0.3333
32.		324	0.1280
33.		325	0.1652
34.		· 326	0.2685
35.		327	0.3016
36.		328	0.3333
37.		329	0.3140
38.	•	330	0.3333
39. ————		332	0.3347
		Total	10.4872 Hectares

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-secion (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval

Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely:

fo	llowing Chairperson and Members, na	mely:—
	1. Development Commissioner of the Special Economic Zone	Chairperson ex-officio
	2. Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of Under Secretary to the Government of India	—Member, ex-officio
.3	3. Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone	—Member, ex-officio
4	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, ex-officio
5.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	Member, ex-officio
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of India	—Member, ex-officio
7.	Two Officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State Government	Member, ex-officio
8.	Representative of the Developer of the zone	—Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 9th day of September, 2011 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 2/143/2006-SEZ] ANUP WADHAWAN, Jt. Secy.